



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2001/आश्विन 16, 1923

No. 274]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2001/ASVINA 16, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2001

**विषय :—**कतर से कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

**सं. 55/1/2001-डीजीएडी.—**मै0 अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमआईए) ने घरेलू उद्योग की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर

पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा एवं संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें कतर (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से कास्टिक सोडा के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और जांच शुरुआत की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद कतर मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साईड है जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के रूप में जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक रसायन है तथा साबुनी, तेज अल्कलाईन

गंधहीन रसायन है। कार्बोस्टिक सोडा का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि लुग्दी तथा कागज अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, सूत तथा लांडरी साबुन डिटरजेंट, रंजक पदार्थों, औषधियों एवं भेषजों का विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि। कार्बोस्टिक सोडा दो स्वरूपों अर्थात् क्षारोदक घोल एवं ठोस रूप में पाया जाता है। वर्तमान जांच में कार्बोस्टिक सोडा के सभी स्वरूप शामिल हैं।

कार्बोस्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसके अलावा, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार शीर्ष 281511 तथा 281512 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

## 2. घरेलू उद्योग की स्थिति:

यह याचिका घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई है। भारत में कार्बोस्टिक सोडा के लगभग 40 घरेलू विनिर्माता हैं। यह एसोसिएशन भारत में कार्बोस्टिक सोडा के लगभग सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है। याचिका का पांच घरेलू उत्पादकों द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया है अर्थात्

- ( i ) मै0 ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि0, नागदा, मध्य प्रदेश,
- ( ii ) गुजरात अलकलिस एंड कैमिकल्स लि0, वड़ोदरा, गुजरात
- ( iii ) सर्च कैम इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई
- ( iv ) डीसी डब्ल्यू लि0, मुम्बई
- ( v ) इंडियम रेयॉन एंड इंडस्ट्रीज लि0, वेरावल, गुजरात

ये याचिकाकर्ता कंपनियां संबद्ध वस्तु के उत्पादन के 33.9% का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए उनके पास पाटनरोधी नियमों के नियम 5(क) तथा (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है।

3. शामिल देश: वर्तमान जांच में शामिल देश कतार है (जिसे इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है)।

## 4. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल सम्बद्ध देश द्वारा उत्पादित, वहां के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है क्योंकि दोनों का अदल-बदल कर इस्तेमाल किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है।

## 5. सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ताओं ने कास्टिक सोडा के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर कतर में सामान्य मूल्य का दावा किया है। संबद्ध वस्तु के जांच के उद्देश्य के लिए प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

## 6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्त्ता ने भारत के एक व्यापारी द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के अंतिम उपभोक्ताओं को किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना-द्वार, पर निर्यात कीमत निकालने के लिए याचिकाकर्त्ता ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, ऋण, पत्तन खर्चों, कमीशन तथा स्वदेशी भाड़े के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। जांच शुरुआत के उद्देश्य से उपर उल्लिखित समायोजनों सहित कारखाना द्वार पर कीमत का संदर्भ लिया गया है।

7. पाटन मार्जिन: इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य, उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस कीमत पर इसका भारत को निर्यात किया गया है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि स्थापित क्षमता तथा कतर में निर्यातकों द्वारा मुक्त रूप से निपटान योग्य संबद्ध वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तु की प्रचलित प्रस्ताव कीमत से कीमत कटौती के रूप में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न होता है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ: उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु<sup>के</sup> आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. जांच की अवधि: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1.1.2001 से 30.9.2001 तक की है।

11. सूचना देना: संबंधित समझे जाने वाले उक्त देश के निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

भारत सरकार,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग,

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 ।

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

12. **समय-सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

13. सभी पार्टियों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर दी गई किसी भी सूचना का आगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना होगा । तथापि, कृपया नोट करें कि ऐसी सूचना पाटनरोधी नियम 7(1) तथा 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी ।

14. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल.बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2001

**Subject :—Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Caustic Soda from Qatar.**

**No. 55/1/2001-DGAD.**— M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of the Domestic industry has filed a petition, in accordance with the customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Caustic Soda from Qatar (herein after called subject country) and has requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping Duties retrospectively from the date of initiation of investigation.

1. **Product involved:** The product involved in the present petition is SodiumHydroxide Commonly known as Caustic Soda (Also referred to as subject goods hereinafter) originating in or exported from Qatar. It is an inorganic chemical and is soapy, strongly alkaline odorless chemical. Caustic Soda finds application in various field like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, and laundry soaps, detergent, dyestuff drugs and pharmaceuticals, petroleum refining, etc. Caustic Soda is available in two forms i.e. Lye and solids. The present investigation covers all forms of Caustic soda.

Caustic Soda is classified under chapter 28 of the custom tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification (Based on Harmonize d Commodity Description and Coding System) Under the heading 281511 and 281512. The classification is,

however indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. **Domestic Industry standing:**

The petition has been filed by the Alkali Manufacturers Association of India representing the Domestic Industry. There are about 40 Domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The Association represents most of all the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The Petition has been expressly supported by five of the domestic producers i.e.

- (i) M/s Grasim Industries Limited, Nagda, MP
- (ii) Gujarat Alkalis & Chemicals Limited, Vadodara Gujarat
- (iii) Search Chem Industries Limited, Mumbai
- (iv) DCW Ltd., Mumbai
- (v) Indian Rayon and Industries Ltd., Veraval, Gujarat

These petitioner companies represent 33.9 % of the subject goods production and thus have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per rule 5(a) and (b) of Anti-Dumping Rules.

3. **Countries Involved:** The country involved in the present investigation is Qatar. (here in referred to as subject country).
4. **Like articles:** The petitioner has claimed that the goods produced by them is a like article to the goods produced, originating in or exported from the subject country as both are used interchangeably. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject country within the meaning of the Rules 2(d)
5. **Normal value:** The Authority notes that the petitioner has claimed normal value of subject goods in Qatar based on the constructed normal value of Caustic Soda. The constructed normal value has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

6. **Export Price**: The petitioner has claimed export price on the basis of an offer given by a trader in India to the end users of the subject goods in India. The petitioner has claimed adjustments on Ocean Freight, Ocean insurance, Credit, Port expenses, Commission, and inland freight to arrive of the ex-factory export price. The ex-factory price with adjustments as indicated above has been referenced for the purpose of initiation.
7. **Dumping margin**: There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.
8. **Injury and Causal Link** : The Authority notes that the installed capacity and availability of sufficiently freely disposable subject goods by exporters in Qatar, coupled with the prevailing offer price of subject goods in India, pose a threat of material injury to the domestic industry by way of price suppression undercutting
9. **Initiation of Anti-Dumping investigation**: The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.
10. **Period of Investigation**: The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.1.2001 to 30.9.2001.
11. **Submission of Information**: The exporters in the said country and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority  
Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.
13. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). Please, however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).
14. **INSPECTION OF PUBLIC FILE:**

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
15. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority